trend that is prevailing in Romania for export of items from India like consumer goods and get items which are abundantly available as the hon. Minister has said. I would like to know whether there is any kind of settlement or an agreement arrived at even without anything in writing, in the course of negotiations.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, in the past, India's principal imports from Romania have been fertilizers, artificial resins and plastic material, some newsprint, iron and steel, electrical machinery, machine tools and transport equipment.

The volume of trade is not high. In the last eight years, the volume of trade has ranged between a low of about 25 million dollars and a high of about 64 million dollars. The volume is not high.

As I said Romania is a small country with a stable population and rich in a large number of natural resources. I have the list. It is in these areas that we think that good relations with Romania would help us in increasing the imports of some of these things from Romania.

As far as the business delegation which visited Romania is concerned, this was under the auspices of the Indo-Romanian Joint Business Council. The last meeting was held on 10th January, 1994. It has identified a large number of areas for co-operation in trade and investment. As of today, there are 14 Indo-Romanian Joint collaborations. These are in the fields of oilfield drilling, thermal power plants, etc.

I am told that a large number of small Indo-Romanian Joint ventures are also operating in Romania. These are funded by NRIs. There is considerable scope for co-operation between the two countries in areas such as oil and petroleum products, chemicals textiles, leather industries, metal works and steel works.

व्यापारिक फर्मों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

194. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या श्रम मंत्री 2 मई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5340 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन फर्मों की ओर बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) इन फर्मों की ओर यह राशि कितने वर्षों से बकाया है; और

(ग) इन फर्मों द्वारा यह राशि जमा न किए जाने से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए और इस संबंध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Outstanding dues of PF from trading firms

s No.	Name of the establishment	Action taken	The period to which dues pertain	No. of employee s
1.	M/s Laxmi Chand Bhagagi (Gujarat)	The EPF dues determined and revenue recovery certificate issued in 1988. Damages have also been levied. A sum of Rs. 1.09 Lakh has been recovered. Recovery action could not be completed because the establishment is under closure / liquidation.	December 1987 to August 1988	400
2.	Kamdhenu Mercantile & Co. (R.O. Maharashtra)	Dues determined and revenue recovery certificate issued. A case under the IPC has been filed. A prosecution case under Section 14 of the EPF & MP Act. 1952 has also been launched for default in the payment of EPF dues.	May, 1992 onwards.	130

s. No	Name of the	Action taken	The period to which dues pertain	No. of employees
3.	M/s CAMPCO Ltd. (Karnataka)	Dues finally determined and an order Section 7-A of the EPF & MP Act was passed for recovery of the EPF dues. The employer has filed writ petitions in the High Court and has got the order of the RPFC stayed. Necessary action is being taken to get the stay orders vacated.	January, 1979 March, 1990	1039

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: सर, यह जो प्रोविडेंट फंड इम्प्लाइज़ का कटता है, यह बहुत सीरियस मसला है और तीन ऐसी ऑरगेनाइजेशन्स या फर्म्स हैं जिनके बारे में यह सवाल पूछा गया है और जो मामला है वह 1569 इम्प्लाइज़ का है। फर्म्स के नाम हैं—मैसर्ज़ लक्ष्मीचन्द्र (गुजरात), कामधेनु मर्केन्टाइल एंड कम्पनी (आर०ओ० महाराष्ट्र) और मैसर्ज़ कैम्पको लि० (कर्नाटक)। इनमें से एक फर्म के खिलाफ तो रिकवरी के लिए ऐक्शन लिया गया है और 1.09 लाख उसमें रिकवर किया गया है, बाकी पैसा गालिबन बाकी है और लिखा गया है कि बाकी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वह इस्टेब्लिशमेंट क्लोज़र पर आ गया है। दूसरे में भी केस फाइल कर दिया गया है और तीसरे में एम्प्लॉयर ने, जो 400 इम्प्लाइज़ का मामला है, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। मेरा कहना यह है कि इम्प्लाइज़ के मामले में यह प्रोविडेंट फंड का जो दफ्तर है अगर इसकी हालत जाकर देखी जाए तो आपको अंदाजा होगा कि बूढ़े लोग, जो रिटायर हो जाते हैं, वहां खड़े रहते हैं, महीनों-महीनों दौड़ते रहते हैं और उनके फंड का पेमेंट नहीं होता। वहां बाकायदा बाहर एजेंट घूमते रहते हैं और जब तक वे अपनी सारी जिंदगी की कमाई से कुछ न कुछ हिस्सा बतौर रिश्वत वहां नहीं पहुंचा देते, तब तक उन बूढ़े लोगों को उनका फंड नहीं मिलता। उसके अलावा जो फर्म्स अपना हिस्सा अदा नहीं करती हैं और इम्प्लाइज़ का हिस्सा भी रख लेती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अमूमन यह पाया गया है कि डिपार्टमेंट ढील करता है और जिसके नतीजे में रिकवरी नहीं होती है यह तीन फर्मों का मामला है, जो सामने आया है, मुल्क में ऐसी हजारों फर्में होंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर कितनी ऐसी फर्में हैं जिनके ऊपर रिकवरी के सिलसिले में केस चल रहा है? यह तो मेरे क्वेश्चन का (ए) पार्ट है।

और पार्ट (बी), मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 1569 इम्प्लाइज़ हैं, उनमें टोटल रिकवरी कितनी आई है, मैं नहीं जानता हूं, यहां तो सिर्फ 1.09 लाख की रिकवरी इन्होंने दिखाई है, लेकिन 400 आदमियों का कोर्ट से स्टे हो गया। अब गरीब आदमी जो काम कर रहा है, सर, उसका फंड तो कट गया और रिकवरी उसकी हो नहीं रही है और आप उसको ले गए अदालत के अंदर या वह अदालत में चला गया, तो क्या सरकार के पास कोई प्रोग्राम है कि आप तो अदालत में उससे लड़ते रहिए क्योंकि आप तो पैसा लेकर अपने इस्तेमाल में रखते हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रोविज़न है कि आप तो केस लड़ते रहिए लेकिन जो इम्प्लाइज़ उससे मुतअस्सिर हैं, उनका फंट आप पूरा सरकार की ओर से अदा करें, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है और आप ऐसा करके उनको पैसा अदा करना चाहते हैं या नहीं?

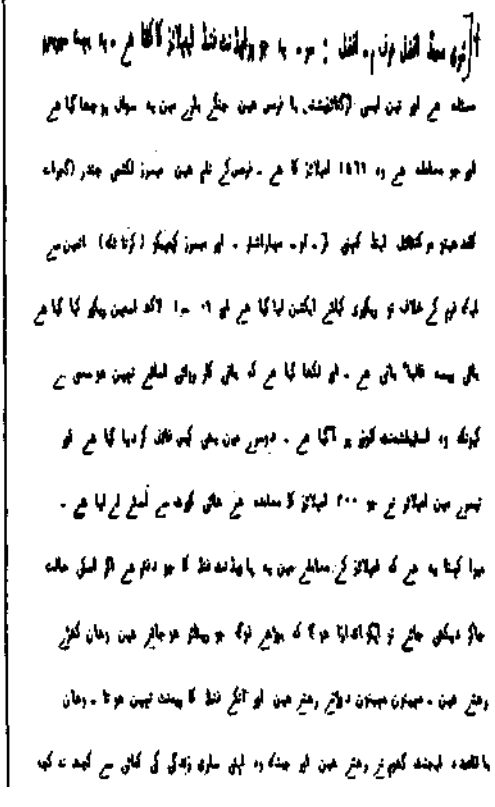

establishments because it is a separate question—1 require notice. There are two parts: one is recovery of arrears, which we are trying to do according to law, and I have narrated the legal actions which we have taken in each case. The second part of the question is, what would happen to those employees who have retired or are retiring? Sir, irrespective of whether the establishment is paying the arrears or not, we do not normally allow the workers to surfer, because we have a Special Reserve Fund out of which, at the time of retirement, the subscriber gets his full dues irrespective of whether the employer has paid the dues or not. So the workers do not suffer.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Please try to be pointed. There are others also. Now all the Members have come for asking questions!

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: सर, मैंने जो इस सिलसिले में पूछा था तथा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, तो बहुत वाजिब जवाब मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि आपने जो यह कहा कि रिटायरमेंट पर आप उनको पूरा पैसा भुगतान कर देंगे। तो अब तक आपके पास ऐसे कितने केसेज हैं तथा ऐसी कितनी फर्मा हैं, जो डिफॉल्ट हुई? और डिफॉल्ट होने के बावजूद चाहे उन पर केस चल रहा है या आप उनसे रिकवरी नहीं कर पाए या भाग गए हैं? तो आपने कितनी फर्मा के कितने एम्प्लोइज को रिटायरमेंट के बाद अब तक पेमेंट कर दिया?

दूसरी बात जो मैंने बहुत शुरू में पूछी थी, सर, वह बहुत इम्पार्टेंट है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि प्रोविडेंट फंड की रिकवरी के सिलसिले में रिटायरमेंट के बाद बूढ़े लोग वहां खड़े रहते हैं तथा तीन-तीन महीना, चार-चार महीना, एक-एक साल तथा दो-दो साल तक उनका पेमेंट नहीं होता। तो क्या आपके पास ऐसी शिकायतें हैं कि वहां पर करप्शन हो रहा है और लोग कमीशन लेकर के गरीब एम्प्लोई का प्रोविडेंट फंड पे करते हैं? अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं तो क्या आपने उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई की है? और अगर वह शिकायतें आप तक नहीं पहुंची हैं तो क्या आप उसकी इंक्वायरी करएंगे?

SHRI P.A. SANGMA: Sir, the question relates to trading concerns, not industrial establishments. As far as trading concerns ace concerned, these are the three concerns which are at default. I don't have information about industrial

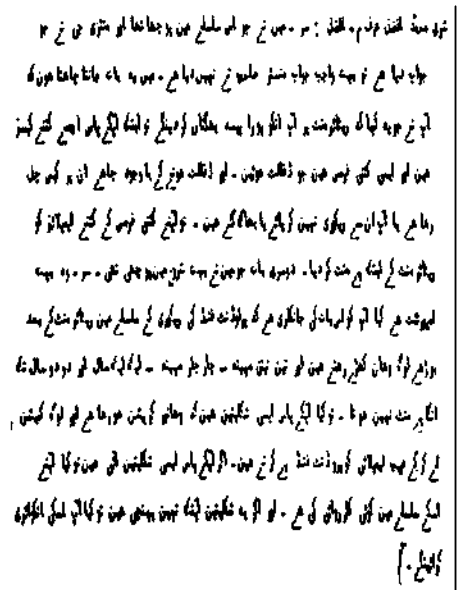

SHRI P.A. SANGMA: Sir, as I have already submitted, the question is regarding three specific trading concerns. I have given the number of workers Involved also, in the main answer. As far as industrial establishments are concerned—a . large number—I do not have the answer with me now. I can supply it to the hon. Member.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, I would like to know from the hon. Minister what is the total amount of dues to be recovered, out of which Rs. 1.09 lakhs have already been recovered. Secondly, since the establishment is under closure or liquidation, what would be the fate of the recovery proceedings? Why could it not be recovered earlier, before the establishment reached the stage of closure or liquidation? Have any coercive methods been applied for the recovery of the dues? The last part of my question is, whether any prosecution is going to be launched against the establishments under the IPC as well as the EPF & MP Act, 1952, for default in payment by the establishments.

SHRI P.A. SANGMA: Sir, the amount outstanding as far as M/s Laxmi Chand Bhagagi is concerned, is Rs. 6.23 lakhs. In the case of Kamdhenu Mercantile & Company it is Rs. 6.34 lakhs and Rs. 6.39 lakhs in the case of M/s CAMPCO Ltd. These are the outstanding arrears of the three companies. As far as the recovery procedure is concerned, ali legal methods which are available are being followed, which I have already narrated in the main answer, except in the case of one company where- they have gone to the court and obtained a stay order. Even in the case of that firm, for one particular period the High Court has not given a stay because it covers three periods, and we are proceeding legally against it.

श्री वीरेन्द्र कटारिया: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मीम अफजल साहब ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत अहम सवाल है क्योंकि मेरे अपने नोटिस में ऐसी बहुत सी बातें आयी है कि बहुत सी फर्मों ने मुलाजिमों का प्रॉविडेंट फंड काटा लेकिन उसको जमा नहीं कराया। मैं पंजाब की कई म्यूनिसिपल कमेटियों के बारे में जानता हूं जो कि लोकल बोडीज़ है, इदारे हैं, उन्होंने अपने मुलाज़मीन का प्रॉविडेंट फंड काटा लेकिन उसको जमा नहीं कराया। मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ऐसा कोई प्रपोज़ल है कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि इस बात को रोका जा सके? इस बात का कई साल के बाद पता लगता है। जैसे एक म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में मैं जानता हूं। पांच साल से बाद पता लगा कि मुलाजिमों का प्राविडेंट फंड. पांच साल से काटा जा रहा है लेकिन उसे पांच साल से जमा नहीं कराया जा रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरिया डिवाइस करने की क्या कोई प्रपोज़ल है कि हर साल पता लग सके कि किस इदारे ने, किस सम्पत्नी ने यह प्राविडेंट फंड जमा नहीं कराया ताकि चैकिंग हो सके और मुलाजिमों का जो नुकसान इस बात से, इस वॉयलेशन से हो रहा है, उसको सख्ती से रोका जा सके।

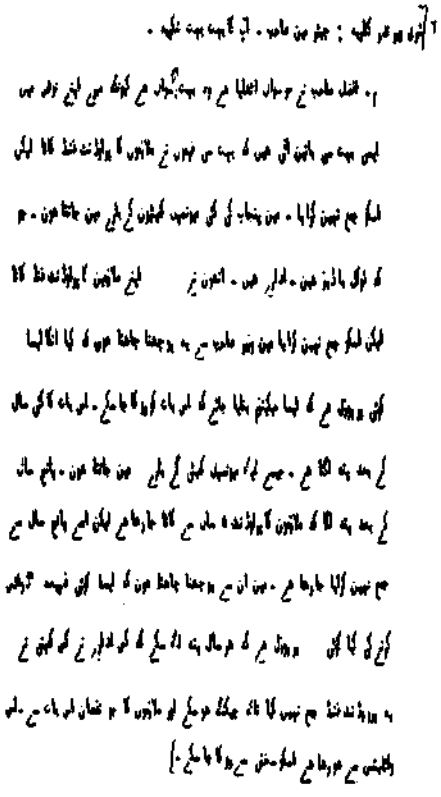

SHRI P. A. SANGMA: Sir, it is true that, in spote of the provisions contained in the Act for recovery, the arrears are mounting. We are concerned about that. The Consultative Committee attached to the Labour Ministry discussed this problem specifically, and it decided to set up a sub-committee to go into the whole question of recovery of the arrears and non-payment of dues. The Committee was headed by hon. Member, Mr. Gurudas Das Gupta himself. It has submitted a report. It has given certain suggestions in order to bring more legal provisions to deal with it more effectively. This report was discussed both in the ESIC as well as in the Central Board of Trustees of the Provident Fund Organisation. At the moment, we are in consultation with the State Governments. We are examining the report of the Das Gupta Committee.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Mr. Chairman, Sir, I have got a question which has a larger implication with regard to provident fund recovery from the defaulting employers. I got an assurance from the hon. Minister in this House. The defaulting employer collected the provident fund not only from the employees but also from the principal employer. It amounts to the tune of a crore of rupees. I have been assured in this House that efforts were being made to get back the money and to pay the money back to the employees. I am surprised that no money has been refunded in the last five years. It appeas that the Provident Fund Commissioner is not pursuing the case. It is in relation to the Paradeep Phosphates Ltd., a Central Government undertaking, where the employer manipulated collection of the provident fund from the principal employer and the employees. The money is still in his pocket, and no effort has been made to collect that money and to pay it back to the principal employer or to the employees till today. Nor this money to be collected. Instead of giving an assurance again, will the Minister take positive steps in this connection?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, if we take the total amount of arrears in percentage terms of the total amount, it comes to less than 1 per cent of the total. The arrears are less than 1 per cent of the total contribution that comes from the Provident Fund. But, even if it is less than 1 per cent, when we speak in terms off the amount, it comes to Rs. 360.99 crores. So, in terms of the amount it is a very big amount. As I said, Sir, we are concerned about this. A lot of steps are being taken; a lot of people have been arrested and a lot of recoveries etc. are going on. But we find that more needs to be done. That is the reason why the Consultative

Committee attached to the Labour Ministry, appointed a Sub-Committee with Mr. Gurudas Das Gupta as its Chairman. They have gone throughout the country and have given a good report and recommendations. They are under examination. I have already stated about it.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: His specific question is with regard to the Paradcep Phosphate Ltd. What is your answer to that?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have stated that this question is about three trading companies. I do not have information about these three trading companies. I do not have information about other establishments.

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Sir, I had put my question with regard to the assurance made by the hon. Minister in this House. No arrest has been made, no coercion has been made and no attept has been made by his Ministry to get back that money. The money is still with the contractor. Sir, I am referring to your assurance in this House.

SHRI P. A. SANGMA: Mr. Chairman, Sir, at the moment I do not have that information. I will cheek it up and inform him.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति महोदय, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के दो भाग है। एक तो जो फर्मों ने प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं कराया। दूसरी बात जो प्रश्नकर्ता ने पूछी थी वह यह थी कि जिनका पैसा जमा हो जाता है, वह भी उनको वापस नहीं मिलता है। तो क्या इसके बारे में आप कोई टाइम लिमिट फिक्स करने जा रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर उनको प्राविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा। अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा दो महीने, 6 महीने, यह एक साल में नहीं मिलता है तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है? जो प्रोविडेंट फंड वापस नहीं करते हैं, सालों साल, जब तक परसन्टेज रिबत का उनको नहीं दिया जाता है तब तक वे प्राविडेंट फंड नहीं देते, तो जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है? क्या इसके लिए आप कोई टाइम लिमिट फिक्स करेंगे कि इतने दिनों के अंदर अंदर उनको मिल जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, the provision already exists for a time-bound payment. Otherwise, if they do not comply with that provision, then an amount of interest is to be paid. That penal provision is very much there But, in spite of all this, the people are defaulting. *(Interruptions)*

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am talking of the officers who are not paying the Provident Fund.

SHRI VIREN J. SHAH: The funds are with the Officers. The funds are with the Provident Fund authorites. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please, give the floor to Mr. Malhotra to ask his specific question.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, I have asked a specific question. The officers administering the Provident Fund do not pay the Provident Fund dues to the employees. What action is he going to take against such officers? By what time are they expected to pay them the Provident Fund amount, which is already there with the Provident Fund authority?

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Sir, he has not understood the question of Mr. Malhotra. *(Interruptions)*

SHRI P. A. SANGMA: I think the question is completely different. Sir, the hon. Member wants to know about the delayed payment of the subscribers from the organisation. The question relates to the default of the trading companies. I do not have that kind of information as to how many complaints are there about the delayed payment of subscribers.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am not asking for that information. I am only asking if you are

going to fix a time limit by which the officers will pay the amount to the subscribers, as there is a lot of Corruption.

SHRI SIKANDER BAKHT: The question is, in fact, about the abuse of the Provident Fund money during this period—the period of your own Ministership. How many officers have been punished for misusing the Prpvident Fund money?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, as I said, I do not have this informaion because this question broadly relates to the default of the three trading concerns.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Mr. Minister, you must have at least the basic knowledge. *(Interruption)*

MR. CHAIRMAN: Please. He has the basic knowledge. Rather more than that.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: No, he does not have. He is not even able to reply. Mr. Malhotra has asked a very simple question.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: The person is not paid even after six months or one year or more unitl and unless he pays the corruption money.

यानी अगर किसी को कोई आफिसर पे नहीं करता है, उस आफिसर के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करते हैं। क्या इसके लिए आप कोई टाइम लिमिट फिक्स करेंगे?

Are you going to fix a time limit by which the money must be paid?

मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजलः आपका प्रोटेक्शन चाहिए। मल्होत्रा साहब ने जो सवाल पूछा है वह बिल्कुल स्पेसिफिक है। मैंने भी शुरू में पूछा था लेकिन उसका जवाब नहीं दे सके और आपने दूसरा सप्लीमेंटरी अलाऊ कर दिया। सवाल यह है कि जिन लोगों को उनका प्रोविडेंट फंड रिटायर होने के भी कई कई सालों तक नहीं दिया जाता—अभी मंत्री जी ने इसका जवाब यह दिया है कि इसके लिए लिमिट है कि उनको तीन महीने में, छह महीने में पेमेंट मिल जाना चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से किसी को पेमेंट नहीं हो पाता है तो क्या उस पेमेंट पर मजीद सूद दिया जाता है?

सरकार तो सूद देने के लिए तैयार है लेकिन आपका जो अफसर बैठा हुआ है वह सूद पर सूद चढ़ाता है लेकिन पैसा उस वक्त तक अदा नहीं होने देता जब तक रिश्वत उसकी जेब में नहीं पहुंच जाती। सवाल यह है कि उन अफसरों के खिलाफ क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे? इसमें आपका भी नुकसान है क्योंकि वह सूद-दर-सूद देता रहता है लेकिन पेमेंट नहीं करता जब तक रिश्वत नहीं पहुंच जाती है।

[Illegible]

SHRI P.A. SANGMA: Sir, actually, this supplementary does not arise out of this question. There are delays in payment of the dues to workers- who are the subscribers. It is a separate question. But I will answer that. Today there has been much improvement because in all the regions, we have gone into computerisation and as a result of computerisation, the service has been much faster. But there is a need for a lot of improvement and we are trying our best.

Decline in Domestic Savings Rate

*195. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Central Statistical Organisation has estimated that the rate of domestic savings has declined sharply in recent years;

(b) if the answer, to (a) is in the affirmative, the factors contributing to this decline; and

(c) the measures Government is contemplating to prevent any further fall in the rate of savings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND